शनिवार 23 मई, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

कोहली इतिहास रचने से सिर्फ 58 रन दूर

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

'कॉकरोच जनता पार्टी' से कोंकणा सेन शर्मा ने बनाई दूरी

Page-05

'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम का व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बेरोजगारी, पेपर लीक और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर केंद्रित इस इंस्टाग्राम अकाउंट ने महज चार दिनों में 93 लाख फॉलोअर्स जुटा लिए। सोशल मीडिया पर इसकी बढ़ती लोकप्रियता ने बड़े राजनीतिक दलों की डिजिटल मौजूदगी को भी चुनौती दे दी है।

'कॉकरोच जनता पार्टी' ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक इंस्टाग्राम अकाउंट 16 मई से वायरल है. इसके 9.3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं. इस मामले में यह भाजपा से आगे हो गया है. कॉकरोच जनता पार्टी बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों पर फोकस करने वाला एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक नया नाम तेजी से चर्चा में है. कॉकरोच जनता पार्टी नाम से शुरू हुआ ऑनलाइन व्यंग्य अभियान कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर बड़ा राजनीतिक ट्रेंड बन गया है. हैरानी की बात यह है कि लॉन्च के महज चार दिनों के भीतर इस अकाउंट ने 90 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए और फॉलोअर्स के मामले में इसने भाजपा के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट को भी पीछे छोड़ दिया. इंस्टाग्राम पर @cockroachjantaparty नाम से चल रहे इस अकाउंट ने 20 मई को 9.3 मिलियन यानी 93 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया. वहीं भाजपा के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल @bjp4india के करीब 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं. हालांकि कांग्रेस अभी भी सोशल मीडिया पर सबसे आगे नजर आ रही है, जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट @incindia पर लगभग 13.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. आम आदमी पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट के करीब 1.9 मिलियन फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं. यह अभियान 16 मई को सामने आया था. बताया जा रहा है कि यह युवाओं द्वारा चलाया गया एक व्यंग्यात्मक आंदोलन है, जिसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कथित टिप्पणी के बाद हुई. शुरुआत में यह अभियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मजाकिया अंदाज में शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते यह युवाओं के बीच वायरल हो गया.

- **'कॉकरोच जनता पार्टी' ने केवल चार दिनों में 93 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जुटाकर बीजेपी के आधिकारिक अकाउंट को पीछे छोड़ दिया।**
- **यह व्यंग्यात्मक डिजिटल अभियान बेरोजगारी, पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ।**

मुख्य रूप से बेरोजगारी, राजनीतिक जवाबदेही, परीक्षा पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं. यही वजह है कि यह अभियान बड़ी संख्या में युवा सोशल मीडिया यूजर्स को आकर्षित करने में सफल रहा.

Advertisement

अकाउंट की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लॉन्च के सिर्फ 78 घंटे के भीतर इसके 30 लाख फॉलोअर्स हो गए थे. इसके बाद यह संख्या तेजी से बढ़ती गई और चार दिनों के भीतर 90 लाख के पार पहुंच गई. खास बात यह है कि इस अकाउंट पर अब तक केवल 56 पोस्ट ही शेयर किए गए हैं. इसके बावजूद इसने कई पुराने और स्थापित राजनीतिक संगठनों के सोशल मीडिया प्रभाव को चुनौती दे दी है. तुलना करें तो बीजेपी के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर अब तक 18 हजार से ज्यादा पोस्ट शेयर की जा चुकी हैं. भाजपा को इंस्टाग्राम पर पीछे छोड़ने के बाद इस अभियान ने सोशल मीडिया पर कई तंज भरे पोस्ट भी किए. एक पोस्ट में लिखा गया- युवाओं की ताकत को कम मत आंकिए.

इसके अगले ही दिन इंस्टाग्राम अकाउंट लॉन्च किया गया और उसके बाद इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती चली गई. यह प्लेटफॉर्म खुद को 'युवाओं का, युवाओं के लिए और युवाओं द्वारा बनाया गया राजनीतिक मंच' बताता है. इसके पोस्ट

धामी बोले- देवभूमि में सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं

सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब सीएम धामी का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सड़कों पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। हमने कहा कि नमाज तय जगह पर ही पढ़ी जानी चाहिए। किसी को भी इस व्यवस्था में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है। इसलिए इस समय सड़कों को धार्मिक प्रदर्शनों का जरिया बिल्कुल भी नहीं बनने दिया जाएगा। हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले सनातनी और चारधाम तीर्थयात्रियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हर चीज़ को केवल वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं, और यह सही नहीं है। इन सभी व्यवस्थाओं में हमें वोट बैंक से ऊपर उठना चाहिए। हम किसी को भी देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे।

'आईएएस अफसरों के बच्चों को आरक्षण क्यों?'

सुप्रीम कोर्ट की क्रीमी लेयर पर सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरक्षण और सामाजिक गतिशीलता के मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि उन बच्चों को आरक्षण क्यों चाहिए जिनके माता पिता पहले से ही आईएएस ऑफिसर्स हैं। कोर्ट ने उन समृद्ध परिवारों द्वारा कोटा लाभों की निरंतर मांग पर सवाल उठाया, जो पहले ही शैक्षिक और आर्थिक उन्नति प्राप्त कर चुके हैं। पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण लाभों से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन बच्चों के लिए आरक्षण की आवश्यकता पर सवाल उठाया जिनके माता-पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं। कोर्ट ने कहा, "अगर दोनों माता-पिता आईएएस अधिकारी हैं, तो आरक्षण की मांग क्यों करें?" अदालत ने टिप्पणी करते हुए जोर दिया कि शैक्षिक और आर्थिक प्रगति से सामाजिक गतिशीलता आती है। शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही सामाजिक गतिशीलता भी आती है। इसलिए बच्चों के लिए आरक्षण की मांग करना कभी भी इससे बच नहीं पाएगा। यह भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें विचार करना होगा। अदालत ने आगे कहा कि कई सरकारी आदेशों में पहले से ही उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का प्रावधान है, लेकिन अब इन बहिष्करणों को चुनौती दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "सामाजिक गतिशीलता मौजूद है। अब सरकार के आदेशों के तहत इन सभी लोगों को आरक्षण से बाहर रखा गया है, और वे इस बहिष्कार पर सवाल उठा रहे हैं। इसे भी ध्यान में रखना होगा।" सुनवाई के दौरान, अदालत ने उन परिवारों द्वारा आरक्षण लाभों की निरंतर मांग पर सवाल उठाया, जिन्होंने कोटा प्रणाली के माध्यम से पहले ही सामाजिक और आर्थिक उन्नति प्राप्त कर ली है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने टिप्पणी की, "छात्रों के माता-पिता अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छी आय कमा रहे हैं, और बच्चे फिर से आरक्षण चाहते हैं। देखिए, उन्हें आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए।"

तसलीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी को अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी तसलीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, उमर खालिद और शरजील इमाम के मामले को सीनियर बेंच के पास भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक है कि सीजेआई नजीब मामले में कानून को स्पष्ट करने के लिए एक उपयुक्त पीठ का गठन करें। विशेष रूप से यूएपीए की धारा 43डी(5) के आवेदन के संबंध में स्पष्टता जरूरी है। उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर अब बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूएपीए कानून के तहत जमानत देने के नियमों को लेकर अलग-अलग फैसलों में मतभेद दिख रहा है, इसलिए अब इस मुद्दे पर बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यूएपीए मामलों में जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को अलग-अलग तरीके से समझा और लागू किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट का ध्यान कई पुराने फैसलों की तरफ दिलाया। कोर्ट ने कहा कि केए नजीब केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज भी पूरी तरह लागू है और यह एक अहम फैसला है। कोर्ट ने साफ कहा कि यूएपीए की धारा 43D(5) जमानत देने की अदालत की ताकत को पूरी तरह खत्म नहीं करती। अगर कोई आरोपी लंबे समय से जेल में है और ट्रायल पूरा होने में काफी समय लग रहा है, तो अदालत जमानत पर विचार कर सकती है।

दिल्ली AIIMS की टीम करेगी द्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम

दिल्ली एम्स की टीम भोपाल जाकर एक्ट्रेस द्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने द्विशा के परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की बात कही है। वहीं, उसका पति भी सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया है। आरोपी के वकील ने हाईकोर्ट में यह जानकारी दी और अग्रिम जमानत की याचिका वापस ले ली। 12 मई की रात द्विशा की मौत के बाद से उसका पति फरार है। द्विशा शर्मा के परिवार के सदस्यों ने बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके दूसरे पोस्टमॉर्टम की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली एम्स की टीम को भोपाल भेजने के लिए कहा है। द्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह और द्विशा के भाई के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो पर द्विशा शर्मा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने कहा, "इसमें सिर्फ सच है। इसमें कोई झूठ नहीं है। उन्होंने सच में वो बातें कही थीं, अच्छी बात ये थी कि वो रिकॉर्ड पर थीं। वो सच में गिरिबाला सिंह और मेरे बीच की बातचीत थी। उनकी मौसी, बड़े भाई, मेरे बड़े भाई और मेरी मां कमरे में मौजूद थे।" इस बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह को उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। गिरिबाला सिंह को निचली कोर्ट से मिली जमानत पर सोमवार को सुनवाई होगी। मध्यप्रदेश सरकार ने उनकी जमानत रद्द करने की याचिका लगाई थी। मेजर हर्षित ने कहा, "बहुत सारी बुरी बातें कहीं गईं, जो उस समय मेरी समझ से बाहर थीं। मैं उन्हें वहीं चैलेंज कर रहा था। लेकिन वे एक जज हैं और उन्हें चैलेंज सुनने की आदत नहीं है। तो, उन्होंने सीधे कहा, "ये लड़का मुझसे ये बातें कैसे कह सकता है? क्या तुम मुझसे क्रॉस-क्वेश्चन कर रहे हो?" मैंने बस उन्हें बताया कि मैं द्विशा का भाई होने के नाते, द्विशा की सास से बात कर रहा हूं और इसलिए मैं उन्हें चैलेंज नहीं कर रहा हूं। ये एक नॉर्मल बातचीत थी और मैं इस पर उसकी राय जानना चाहता था। वो अपनी बात पर अड़ी रहीं और उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। ये बहुत हैरानी की बात थी।"

पर्यटन विभाग के सभी प्रस्तावित विदेशी दौरे तत्काल प्रभाव से रद्द

महाराष्ट्र सरकार ने अपने पर्यटन विभाग और संबद्ध प्रतिनिधिमंडलों के सभी प्रस्तावित विदेशी दौरों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह कदम ईंधन बचाने और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रव्यापी अपील के जवाब में लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशों का भी इसमें पालन किया गया है। राज्य के पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने आज एक बयान में इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र की समग्र आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। देसाई ने सरकारी तंत्र और नागरिकों दोनों से इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हम न केवल सरकारी तंत्र से, बल्कि राज्य भर के नागरिकों से भी ईंधन और विदेशी मुद्रा संरक्षण के इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह करते हैं। मंत्रालय ने इस संबंध में पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक आधिकारिक आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग ने नागरिकों से विदेशी यात्रा के बजाय घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा। राज्य की समृद्ध विरासत और विभिन्न स्थलों को खोजने का अवसर मिलेगा। यह विदेशी मुद्रा के संरक्षण में भी सहायक होगा। साथ ही, ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी को कम करने में मदद मिलेगी। विभाग ने लोगों से जहां संभव हो, सार्वजनिक परिवहन या पर्यावरण-अनुकूल वाहनों का विकल्प चुनने को भी कहा है।

अमेरिका-ईरान डील की आहट से मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद तेज

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की खबर ने दुनिया का ध्यान खींचा है। प्रस्तावित डील में युद्धविराम, हमले रोकने और समुद्री रास्तों की सुरक्षा जैसे अहम बिंदु शामिल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी बातचीत में प्रगति की पुष्टि की है। हालांकि, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब भी कई सवाल बाकी हैं।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अचानक शांति की उम्मीद नजर आई है है। प्रमुख मीडिया संस्थान 'अल अरबिया' ने शुक्रवार को दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच एक अहम समझौते का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसकी घोषणा कुछ घंटों में हो सकती है। अगर यह डील फाइनल हुई तो लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष थम सकता है और पूरा विश्व राहत की सांस लेगा। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित समझौते में सबसे पहले जमीन, समुद्र और हवा में तुरंत पूर्ण युद्धविराम का ऐलान है। दोनों देश एक-दूसरे के सैन्य, नागरिक या आर्थिक ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। मीडिया युद्ध भी बंद होगा। इसके अलावा, समझौते में दोनों पक्षों ने संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देने का वादा किया है। अरब सागर, हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में जहाजों की आजादी बनी रहेगी। साथ ही एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी जो समझौते पर नजर रखेगी और किसी विवाद को सुलझाएगी। समझौता लागू होते ही सात दिन के अंदर बाकी मुद्दों पर बातचीत शुरू हो जाएगी। खबर यह भी है कि अमेरिका धीरे-धीरे अपनी पाबंदियां हटाएगा, लेकिन इसके बदले ईरान को सभी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। समझौता घोषणा के तुरंत बाद लागू माना जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने स्वीडन में नाटो सम्मेलन में कहा- ईरान के साथ डील में कुछ प्रगति हुई है। यह बयान ऐसे समय आया जब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान में अपना कार्यक्रम बढ़ाकर ईरानी विदेश मंत्री से दूसरी बैठक कर चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी जल्द ईरान जा सकते हैं, जब दोनों देश औपचारिक घोषणा करने को तैयार होंगे। हालांकि, समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर बहुत सख्त हैं। उन्होंने पहले कहा था- हम इसे हासिल कर लेंगे। हम इसे नहीं चाहते और न ही इस्तेमाल करेंगे। शायद इसे नष्ट कर देंगे, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। बता दें कि ईरान के पास करीब 900 पाउंड उच्च समृद्ध यूरेनियम है, जिसे और परिष्कृत करके हथियार बनाने लायक बनाया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल इसे अपने लिए बड़ा खतरा मानते हैं। इजराइल लंबे समय से इस कार्यक्रम का विरोध कर रहा है।

पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हत्या

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हत्या कर दी गई है। मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलवारों ने उसे गोली मार दी। सूत्रों के अनुसार इस हमले में उसकी मौत हो गई। वह पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी था। इस आतंकी की हत्या से जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को एक और बड़ा झटका लगा है। अरजमंद गुलजार उर्फ बुरहान हमजा प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-बद्र के प्रमुख कमांडरों में से एक था।सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वह लंबे समय से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में शामिल था और दक्षिण कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने वाले प्रमुख चेहरों में गिना जाता था। अरजमंद गुलजार मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के रत्नीपोरा इलाके का रहने वाला था। बताया जाता है कि वह करीब 7 साल पहले वैध दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तान गया था, जहां उसने आतंकी संगठन अल-बद्र जॉइन कर लिया। बाद में वह संगठन का ऑपरेशनल कमांडर बन गया और पाकिस्तान से बैठकर कश्मीर में आतंकियों की भर्ती, फंडिंग और हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क चलाने लगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसे लंबे समय से "मोस्ट वांटेड" सूची में रखा हुआ था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 में उसे आधिकारिक रूप से आतंकवादी घोषित किया था। मंत्रालय के अनुसार वह पुलवामा और दक्षिण कश्मीर में आतंक फैलाने, युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती कराने और आतंकवाद के लिए आर्थिक सहायता जुटाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था।

द्विशा शर्मा केस: पति समर्थ सिंह पर कसा शिकंजा

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

द्विशा शर्मा केस में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। मृतक द्विशा के पति समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में दायर अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। वह भोपाल जिला कोर्ट में कभी भी सरेंडर कर सकता है। समर्थ के सरेंडर की खबरों के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही खुलासा होगा कि आखिर द्विशा की मौत का राज क्या है। क्या वाकई द्विशा ने आत्महत्या की है या फिर द्विशा के परिवार के लगाए आरोप के मुताबिक उसकी हत्या की गई है। बता दें कि इस मामले में द्विशा का पति समर्थ सिंह मुख्य आरोपी है। जिस पर अब कानूनी रूप से शिकंजा कस चुका है। हाईकोर्ट और वरिष्ठ वकीलों के सख्त रवैये को देखते हुए समर्थ सिंह ने जहां पहले अपने अधिवक्ता से कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने का लिखित आवेदन किया। माननीय अदालत ने इस निवेदन को विधिवत सिवाकर कर उसकी अग्रिम जमानत याचिका आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दी है। सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद अब मुख्य आरोपी समर्थ सिंह ने जल्द ही भोपाल जिला कोर्ट में कानूनी तौर पर आत्मसमर्पण करने की तैयारी की है। अब समर्थ सिंह कभी भी कोर् में सरेंडर कर सकता है। बताया जा रहा है कि हाईप्रोफाइल इस केस की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ वकील तुषार मेहता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्विशा शर्मा के पक्ष में मजबूत दलीलें पेश कीं। हाईकोर्ट जज अवनींद्र सिंह की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए केस के सभी अहम पहलुओं को सुनने के बाद जहां सास गिरिबाला सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं पीड़ित परिवार की द्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम की याचिका को भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद सोमवार तक सुनवाई को स्थगित कर दिया है। अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी।मामला 12 मई का है। जब नोएडा की रहने वाली 33 वर्षीय द्विशा शर्मा (Twisha Sharma) अपने ससुराल भोपाल के कटारा हिल्स में घर में ही फंदे पर लटकी पाई गई थीं। द्विशा की शादी 5 महीने पहले ही भोपाल के एक वकील समर्थ सिंह के साथ हुई थी।

मार्को रुबियो ने कहाभारत जितनी ऊर्जा खरीदना चाहेगाअमेरिका उतनी बेचने के लिए तैयार

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिका ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने के संकेत दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि भारत जितनी ऊर्जा खरीदना चाहेगा, अमेरिका उतनी बेचने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर लगातार बातचीत चल रही है। मियामी में रुबियो ने कहा, 'हम भारत को उतनी ऊर्जा बेचना चाहते हैं, जितनी वह खरीदना चाहे। अमेरिका इस समय रिकॉर्ड स्तर पर ऊर्जा उत्पादन और निर्यात कर रहा है।'रुबियो 23 से 26 मई तक भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। उनके कार्यक्रम में व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि वॉशिंगटन चाहता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिकी ऊर्जा को अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा बनाए। उन्होंने यह भी कहा कि वेनेजुएला के तेल को लेकर भी अवसर मौजूद हैं। रुबियो ने कहा, 'हम भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को और बढ़ाना चाहते हैं। इस दिशा में पहले से बातचीत चल रही है। हमें लगता है कि वेनेजुएला के तेल को लेकर भी संभावनाएं हैं।'रुबियो ने यह भी माना कि भारत वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर तरीके से संभाल रहा है। खास तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के कारण दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा है और भारत इस चुनौती से निपटने के लिए अलग-अलग विकल्प तलाश रहा है। भारत-अमेरिका संबंधों की तारीफ करते हुए रुबियो ने भारत को 'महान सहयोगी और मजबूत साझेदार' बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और उनका भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण है।

अब्बास अराघची ने पाकिस्तान के गृह मंत्री नक़वी से एक और बैठक की

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

वाशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही युद्धविराम वार्ता के बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार को तेहरान में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी से एक और बैठक की। नकवी ने अब्बास अराघची से मुलाकात कर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की ताकि दोनों पक्ष पश्चिम एशिया के इस संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकें। फिलहाल, तेहरान पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिका द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान ने अभी तक प्रस्ताव पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले, एक ईरानी अधिकारी ने अल जज़ीरा को बताया था कि वार्ताकार एक समझौते पर पहुंचने के बहुत करीब हैं। इससे पहले, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मौजूदा बातचीत पर वाशिंगटन के दृष्टिकोण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने ईरानी राजधानी में होने वाली आगामी चर्चाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इसलिए उम्मीद है कि इससे बातचीत आगे बढ़ेगी। रुबियो ने एक ठोस समझौते को हासिल करने पर अमेरिकी प्रशासन के प्राथमिक फोकस पर जोर देते हुए कहा, "राष्ट्रपति की प्राथमिकता

एक अच्छा समझौता करना है, यही उनकी प्राथमिकता है। यह हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है। अगर हम एक अच्छा समझौता कर पाते हैं, तो यह बहुत अच्छा होगा। राजनयिक प्रगति में कुछ सकारात्मक संकेतों को स्वीकार करते हुए, रुबियो ने तात्कालिक स्थिति के बारे में संयमित और यथार्थवादी दृष्टिकोण बनाए रखा। उन्होंने आगे कहा, "कुछ अच्छे संकेत हैं, लेकिन मैं अत्यधिक आशावादी भी नहीं होना चाहता, इसलिए देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में क्या होता है। गौरतलब है कि आईएसएनए की रिपोर्ट के अनुसार, शांति वार्ता जारी रहने के कारण पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर गुरुवार को तेहरान की यात्रा कर सकते हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार, पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन के बीच संदेशों के आदान-प्रदान में मध्यस्थता करना जारी रखे हुए है, और कहा कि ईरान के मूल 14-सूत्रीय ढांचे के आधार पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कड़े संदेश के बाद राजनयिक वार्ता का यह नवीनतम दौर शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने ईरान से समझौते को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता दिखाने का आह्वान किया था।

संपादक की कलम से

लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित व्यवस्था नहीं है। इसकी असली ताकत जनता के उस भरोसे में छिपी होती है कि उसका मत स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी है। जब चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, तब मामला केवल किसी दल की जीत या हार का नहीं रहता, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता भी बहस के केंद्र में आ जाती है। हाल के दिनों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठे आरोपों ने इसी चिंता को फिर सामने ला दिया है। यह कहा जा रहा है कि कई बार केवल कुछ सीटों का परिणाम ही नहीं, बल्कि पूरी सत्ता का स्वरूप भी चुनावी प्रक्रियाओं से प्रभावित हो सकता है। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी, मतदान के दौरान कथित अनियमितताएं और संस्थागत निष्पक्षता पर उठते सवाल लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत हैं। यदि जनता को यह महसूस होने लगे कि उसका मत पूरी ईमानदारी से दर्ज नहीं हो रहा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव कमजोर पड़ने लगती है। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग माना जाता है। करोड़ों मतदाता हर चुनाव में उत्साह से भाग लेते हैं और इसी भागीदारी से लोकतंत्र को शक्ति मिलती है। लेकिन यही शक्ति तब कमज़ोर होने लगती है जब चुनावी प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा होता है। संदेह चाहे वास्तविक हो या केवल राजनीतिक विवाद का हिस्सा, उसका असर आम नागरिक के मन पर पड़ता है। मतदाता के मन में यदि यह सवाल पैदा हो जाए कि उसका मत सही अर्थों में गिना भी जाएगा या नहीं, तो यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर मानी जाएगी।यह भी सच है कि चुनावी हार के बाद आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कोई नई बात नहीं है। लंबे समय से यह प्रवृत्ति देखी जाती रही है कि जब परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं आते, तो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन लोकतंत्र में केवल आरोप पर्याप्त नहीं होते। यदि किसी को चुनावी अनियमितताओं पर संदेह है, तो उसके समर्थन में प्रमाण और तथ्य भी सामने आने चाहिए। बिना ठोस आधार के लगाए गए आरोप केवल राजनीतिक वातावरण को और अधिक अविश्वास से भरते हैं। दूसरी ओर, चुनाव कराने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। केवल निष्पक्ष होना पर्याप्त नहीं, बल्कि जनता के सामने निष्पक्ष दिखाई देना भी उतना ही आवश्यक है। मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया, मतगणना और परिणामों की घोषणा तक हर स्तर पर अधिक पारदर्शिता समय की मांग है। यदि कहीं भी शंका की गुंजाइश रह जाती है, तो उसे दूर करने के लिए संस्थाओं को तत्परता से सामने आना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास है। यह विश्वास टूटने लगे तो चुनाव केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखा जाए। लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब आम नागरिक को यह भरोसा होगा कि उसका मत किसी भी परिस्थिति में उसकी आवाज़ बनकर सामने आएगा। यही भरोसा लोकतंत्र की असली नींव है और इसकी रक्षा करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

हरभजन सिंह के आरोपों से पंजाब की राजनीति में मचा सियासी तूफान

बीजेपी सांसद हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी पर राज्यसभा सीटों और कैबिनेट पदों के बंटवारे में सौदेबाजी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में राजनीतिक लाभ के लिए फैसले किए गए और सही समय आने पर वह पूरी सच्चाई उजागर करेंगे।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पंजाब की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान बीजेपी राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी पर राज्यसभा सीटों और कैबिनेट पदों के बंटवारे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में राजनीतिक लाभ के लिए कई फैसले किए गए और सही समय आने पर वह इन सौदों से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक करेंगे। यह बयान उस समय आया जब आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। हरभजन सिंह के इस बयान ने पंजाब की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब में राज्यसभा सीटों को लेकर कई ऐसे फैसले हुए जिनकी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सीटें बेची गईं और कई लोगों को राजनीतिक फायदे पहुंचाए गए। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन कहा कि समय आने पर वह बताएंगे कि किसे क्या लाभ मिला और किसके कहने पर फैसले लिए गए। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब AAP समर्थक लगातार उनसे राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। हरभजन सिंह ने केवल राज्यसभा सीटों तक ही अपने आरोप सीमित नहीं रखे। उन्होंने पंजाब में कैबिनेट पदों के बंटवारे को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कुछ मंत्री पद निजी हितों को ध्यान में रखकर दिए गए और इससे पंजाब के हितों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने अपने फायदे के लिए पूरे राज्य को लूट लिया। इस बयान के बाद पंजाब की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल भी अब इन आरोपों को लेकर AAP नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हरभजन सिंह हाल ही में छह अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ AAP छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद से AAP समर्थकों ने उन पर लगातार निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर उन्हें गद्दार कहकर आलोचना की गई और आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने सांसदों को दल बदलने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की। हरभजन ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने किसी नेता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया, जबकि उन्हें लगातार निशाना बनाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब की जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है और वह उचित समय पर सभी तथ्यों को सामने रखेंगे।

मनीष सिसोदिया द्वारा भाजपा पर निशाना साधने के बाद एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज सिंह की गिरफ्तारी और बाद में रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया द्वारा भाजपा पर निशाना साधने के बाद शुक्रवार को एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। सिसोदिया ने एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा पर तीखा हमला करते हुए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और मामले में गिरफ्तारियों के संचालन पर सवाल उठाए। सिसोदिया ने लिखा कि सिंह और उनका परिवार भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने पुलिस मुठभेड़ों, ईडी-सीबीआई की छापेमारी और फर्जी मामलों में गिरफ्तारियों का भी जमकर समर्थन किया होगा। उन्होंने इन सब पर भी तालियां बजाई होंगी। भाजपा को उनकी तालियों से और भी ज्यादा हिम्मत मिली होगी - कि जब चाहे, जिस आरोप में चाहे, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, मुठभेड़ कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर राज सिंह को रिहा नहीं किया जाता तो "अंधभक्त मीडिया" "पुलिस द्वारा आरोपी को गोली मारने" की घटनाओं को प्रचारित कर देता। लेकिन शुक्र है भगवान का। वे बच गए। वरना, भाजपा के अंधभक्त मीडिया पूरे देश में शोर मचा रहा होता कि भाजपा की पुलिस ने मास्टरमाइंड को मार गिराया है। भाजपा के लिए जो वाहवाही वे दे रहे थे, वही उनके अपने ही मुठभेड़ में गोलियों में तब्दील होने वाली थी। हत्या मामले में गिरफ्तार राज सिंह के इस आरोप के बाद ये बयान सामने आया है कि पुलिस ने गलत पहचान के आधार पर उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया था और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद एएनआई से बात करते हुए सिंह ने दावा किया कि अयोध्या से अपनी मां के साथ लौटते समय उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन पर ऐसे अपराध को कबूल करने का दबाव डाला गया था जो उन्होंने किया ही नहीं था। सिंह ने कहा कि मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था, मुझे किसी और राजकुमार सिंह समझ लिया गया था। मैं अपनी मां के साथ अयोध्या दर्शन के लिए गया था। घर लौटते समय पुलिस की एक टीम ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, न ही सबूत मांगे। उन्होंने मुझे मुठभेड़ की धमकी दी और जबरन कबूल करवाने की कोशिश की।

दिल्ली में बड़ा फैसला: जल बोर्ड शुल्कों में राहत

13 साल बाद फिर शुरू हुए नए राशन कार्ड आवेदन

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के बुनियादी ढांचा शुल्कों में बड़े पैमाने पर युक्तिकरण की घोषणा की। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस निर्णय की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "...हमने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लगाए जा रहे बुनियादी ढांचा शुल्कों को पूरी तरह से युक्तिकरण करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब, पानी और सीवर के लिए बुनियादी ढांचा शुल्क केवल पानी की आवश्यकता के आधार पर लगाया जाएगा... शुल्क पानी की आवश्यकता के अनुसार होगा। बुनियादी ढांचा शुल्क केवल नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर ही लगाया जाएगा... खुले क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता को बुनियादी ढांचा शुल्क में शामिल नहीं किया जाएगा। बाद में दिन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी में आधुनिक मुखमेलपुर पार्क की आधारशिला रखी, "जिसका निर्माण लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर कहा कि लगभग 3 एकड़ में विकसित किए जा रहे इस पार्क में पैदल मार्ग, झोपड़ियां, एक तालाब और आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं होंगी। इस बीच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को घोषणा की कि नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया 15 मई से बड़े पैमाने पर फिर से शुरू हो गई है, जिससे लगभग 13 वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि पात्र और जरूरतमंद परिवारों से आवेदन करने का आग्रह किया और कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय विजन को लागू कर रही है ताकि कल्याणकारी लाभ उन लोगों तक पहुंचें जिन्हें वास्तव में इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों को जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से ई-जिला पोर्टल के माध्यम से शुरू हो गए हैं। अतीत में जमा किए गए पुराने आवेदन भी आवेदकों को उनके लॉगिन प्रोफाइल के माध्यम से वापस कर दिए गए हैं। आवेदक वैध पारिवारिक आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ उन्हें अपडेट और पुनः जमा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली का व्यापक ऑडिट किया, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुईं। कुल 7,71,384 अपात्र फर्जी लाभार्थियों की पहचान की गई।

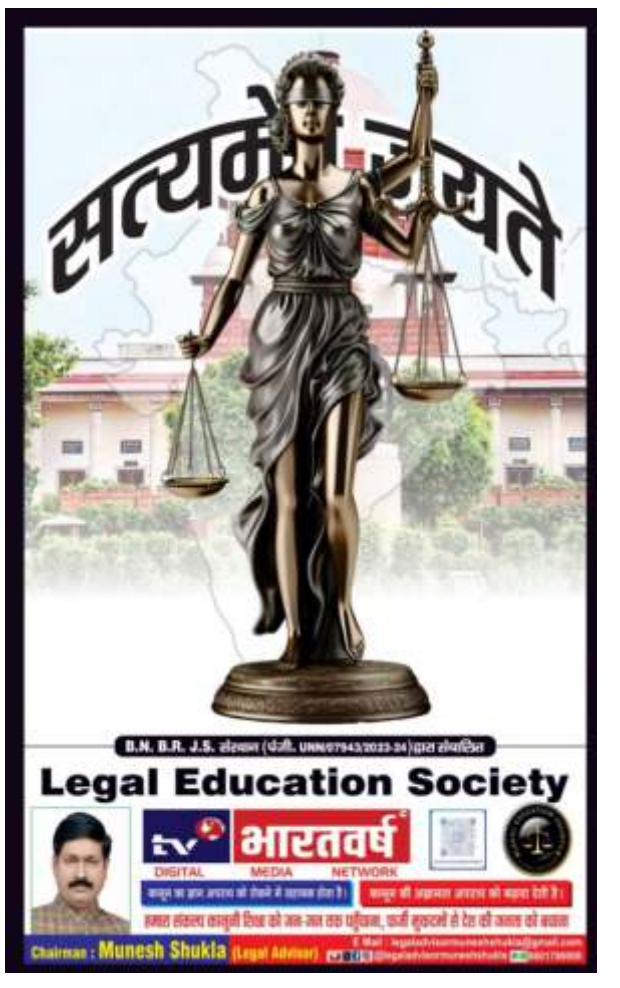

सिर्फ SAT-GRE काफी नहीं

अमेरिका में एडमिशन की नई कुंजी बना कैपस्टोन प्रोजेक्ट

12वीं के बाद अधिकांश छात्रों का सपना होता है कि वे विदेश में पढ़ाई करें और खासकर अमेरिका जैसे देश में जाकर अपना करियर बनाएं. लेकिन यह सपना सिर्फ अच्छे मार्क्स से पूरा नहीं होता. इसके लिए SAT, ACT (यूजी के लिए), GRE या GMAT (पीजी के लिए) और अंग्रेजी दक्षता के लिए IELTS या TOEFL जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं. हालांकि, अब सिर्फ एग्जाम क्लियर करना ही काफी नहीं है,क्योंकि यूनिवर्सिटीज ऐसे छात्रों को प्राथमिकता देते हैं जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स भी हों. और इसी में सबसे अहम भूमिका निभाता है कैपस्टोन प्रोजेक्ट, जो उनकी योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करता है. ऐसे में अगर आप भी अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं या बैचलर्स/मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं, तो आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए. इसे समझना जरूरी है क्योंकि यह आपकी पढ़ाई की प्लानिंग, प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ाने और ग्रेजुएशन के बाद करियर बनाने में काफी मदद करता है. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं. कैपस्टोन प्रोजेक्ट एक ऐसा अकादमिक प्रोजेक्ट होता है, जो किसी कोर्स के अंत में कराया जाता है, जहां एग्जाम के जरिए सिर्फ कोर्स से जुड़ी जानकारी को परखा जाता है और इसका उद्देश्य छात्र की पूरी सीख को एक साथ परखना होता है. यह प्रोजेक्ट यह दिखाता है कि छात्र ने अपने विषय को कितनी गहराई से समझा है और वह उसे वास्तविक जीवन में कैसे लागू कर सकता है. यह प्रोजेक्ट यूजी और पीजी दोनों स्तरों पर अहम होता है. आसान शब्दों में कहें तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट हर डिग्री के लिए जरूरी होता है. यह एक सेमेस्टर या पूरे साल चलने वाला प्रोजेक्ट होता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि कैपस्टोन प्रोजेक्ट केवल थ्योरी तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें रिसर्च, प्रैक्टिकल वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल होती है. यानी छात्र को किसी वास्तविक समस्या पर काम करना होता है और उसका समाधान तैयार करना होता है. कैपस्टोन प्रोजेक्ट के कई प्रकार होते हैं. इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, बिजनेस प्लान, डिजाइन प्रोटोटाइप, केस स्टडी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर क्रिएटिव प्रोजेक्ट शामिल हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग के छात्र कोई मशीन या सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं, जबकि मैनेजमेंट के छात्र बिजनेस केस स्टडी पर काम करते हैं. वहीं आर्ट्स या मीडिया के छात्र डॉक्यूमेंट्री, फिल्म या कंटेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं. वही प्रोजेक्ट का टाइप चाहे जो भी हो, इसका मुख्य लक्ष्य एक ही रहता है: यह साबित करना कि स्टूडेंट गंभीर रूप से सोच सकता है, जटिल समस्याओं को हल कर सकता है और अपनी फील्ड में प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकता है. अमेरिका की यूनिवर्सिटीज कैपस्टोन प्रोजेक्ट को खास महत्व देती हैं, क्योंकि वहां की शिक्षा प्रणाली में प्रैक्टिकल लर्निंग को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है. रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रोजेक्ट छात्रों के पोर्टफोलियो का मजबूत हिस्सा बनता है और एडमिशन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है. इससे यूनिवर्सिटी को यह समझने में मदद मिलती है कि छात्र सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं है, बल्कि वह अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया में लागू करने की क्षमता भी रखता है. कैपस्टोन प्रोजेक्ट का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है. इसमें टीमवर्क, रिसर्च, डेटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन जैसी स्किल्स विकसित होती हैं. यही स्किल्स आगे चलकर नौकरी पाने में मदद करती हैं. कई बार कंपनियां ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखकर ही छात्रों को इंटर्नशिप या जॉब ऑफर कर देती हैं. वही अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि केवल एग्जाम पास करना ही काफी नहीं है. एक मजबूत कैपस्टोन प्रोजेक्ट आपकी प्रोफाइल को अलग बनाता है और एडमिशन के मौके बढ़ा देता है.

एसआरएच को टॉप-2 में पहुंचने के लिए क्या करना होगा?

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का 67वां मुकाबला आज शुक्रवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये दोनों टीमें प्लेऑफ में पहले ही जगह बना चुकी हैं। अब आरसीबी की नजर इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को अधिक मजबूत करते हुए क्वलीफायर-1 बनने पर होगी तो एसआरएच भी टॉप-2 के साथ लीग चरण को खत्म करना चाहेगी। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन 13 में से 8 मुकाबले जीते हैं। यह टीम 16 अंकों के साथ फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मौजूद है। वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 में से 9 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है।18 अंकों के साथ आरसीबी प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर है। आरसीबी अगर इस मैच को अपने नाम कर लेती है, तो यह टीम नंबर-1 रहते हुए क्वालीफायर-1 खेलेगी। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत खास नहीं रही थी। इस टीम ने शुरुआती 4 में से 3 मैच गंवा दिए थे, जिसके बाद लगातार 5 मुकाबले जीतकर अपनी स्थिति को सुधारा। हैदराबाद के पिछले चार मुकाबलों को देखें, तो इस टीम ने 2 मैच अपने नाम किए हैं। एसआरएच इस मुकाबले को जीतकर शीर्ष-2 में अपनी जगह बना सकती है, लेकिन उसे बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। यानी एसआरएच को आरसीबी के खिलाफ मैच में कम से कम 87 रन से जीत या फिर 11 ओवर या उससे कम में टारगेट को हासिल करना होगा।

पाकिस्तान टीम से मोहम्मद रिजवान की हुई छुट्टी

तीन साल की कड़ी मेहनत अब लाई रंग

एक तरफ जहां खेल प्रेमियों को 12 जून से शुरू होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने का इंतजार काफी बेसब्री से है तो वहीं इसी बीच दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रोते हुए एक वीडियो सामने आया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप से ठीक पहले रोनाल्डो सऊदी प्रो लीग में अल-नस्र क्लब की तरफ से खेलते हुए उसे पहला खिताब जिताने में 22 मई को सफल हुए। रोनाल्डो इस मुकाबले में जीत के बाद मैदान पर काफी भावुक दिखाई दिए जिसमें वह अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सके और रोने लगे। दरअसल क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस क्लब के साथ साल 2023 में जुड़े थे, जिसमें टीम लगातार खिताब जीतने से चूक रही थी लेकिन अब तीन साल के लंबे इंतजार के बाद रोनाल्डो अपनी टीम को विजेता बनाने में कामयाब रहे हैं। सऊदी प्रो लीग में अल नस्र क्लब जिसका हिस्सा क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं उनका 22 मई को रियाद के अलअव्वल पार्क में दमाक से मुकाबला था। इस मैच का पहला गोल खेल के 33वें मिनट में अल नस्र की तरफ से सादिओ माने ने किया तो वहीं 51वें मिनट में दूसरा गोल किंग्सले कोमन की तरफ से आया जिसके दम पर अल नस्र ने 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। दमाक की तरफ से मुकाबले का पहला गोल 57वें मिनट में मोलें स्लैया की तरफ से और मैच 2-1 पर आ गया। यहां से क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू देखने को मिला जिन्होंने मुकाबले को एकतरफा करने में अहम भूमिका अदा की और खेल के 62वें और फिर 80वें मिनट में गोल करने के साथ अल नस्र को 4-1 से जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की।

विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने के फैसले पर फटकार लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को घरेलू प्रतियोगिताओं के लिए पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने के फैसले पर फटकार लगाई और मातृत्व अवकाश के बाद महासंघ द्वारा चयन के पुराने मानदंडों से हटकर फैसला लेने पर सवाल उठाया। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को भाग लेने की अनुमति देने की पूर्व प्रथा से डब्ल्यूएफआई का हटना "बहुत कुछ कहता है", और केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मातृत्व अवकाश से वापसी कर रही फोगाट को आगामी एशियाई खेलों के चयन परीक्षणों में भाग लेने की अनुमति दी जाए।बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि देश में मातृत्व का सम्मान किया जाता है और फेडरेशन को "बदले की भावना" से काम नहीं लेना चाहिए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब डब्ल्यूएफआई ने 9 मई को फोगाट को 15 पन्नों का कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उन पर अनुशासनहीनता, डोपिंग विरोधी प्रक्रियाओं का उल्लंघन और पेरिस ओलंपिक के दौरान भारतीय कुश्ती की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।फेडरेशन ने डोपिंग विरोधी नियमों के तहत संन्यास से वापसी करने वाले खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य छह महीने की नोटिस अवधि का हवाला देते हुए उन्हें 26 जून तक घरेलू प्रतियोगिताओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। फोगाट ने इस फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि डब्ल्यूएफआई ने चयन मानदंडों में बदलाव किया है ताकि 30-31 मई को होने वाले एशियाई खेलों के ट्रायल्स में केवल हाल ही में घरेलू पदक जीतने वाली खिलाड़ियों को ही शामिल किया जा सके। गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवकाश के कारण वह इन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाईं। प्रतिबंध के बावजूद, उन्होंने गोंडा में आयोजित राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लिया।

कोहली इतिहास रचने से सिर्फ 58 रन दूर

इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है जिसमें लीग स्टेज के सिर्फ चार मुकाबले खेले जाने बाकी हैं और उसके बाद प्लेऑफ मैचों की शुरुआत होगी। 22 मई को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के बीच में मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें दोनों ही टीमें प्लेऑफ के लिए अपनी जगह को पहले ही पक्की कर चुकी हैं, लेकिन इस मैच का परिणाम तय करेगा का पहला क्वालीफायर किन दो टीमों के बीच में खेला जाएगा। ऐसे में आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला काफी अहम रहने वाला है। इस मैच में आरसीबी टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं जिसमें उनके पास आईपीएल में एक और इतिहास रचने का मौका है।विराट कोहली जिनके नाम आईपीएल के 19 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है, उनका लगभग हर सीजन में बल्ला जमकर बोलते हुए नजर आया है। आईपीएल 2026 में कोहली ने लीग स्टेज में अब तक 13 मुकाबलों में खेलते हुए 54.20 के औसत से कुल 542 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से एक शतकीय और चार अर्धशतकीय पारियां देखने को मिली हैं। ऐसे में कोहली यदि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मुकाबले में अपने शानदार फॉर्म को जारी रखने में कामयाब होते हैं और 58 रन बना लेते हैं तो वह आईपीएल में लगातार चार सीजन में 600 रनों का आंकड़ा पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। अभी इस मामले में कोहली संयुक्त रूप से क्रिस गेल, डेविड वॉर्नर और केएल राहुल के साथ पहले नंबर पर ही जिसमें इन सभी ने तीन-तीन बार ऐसा किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आईपीएल 2026 में मैदान पर शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें वह प्लेऑफ के लिए जगह पक्की करने वाली पहली टीम भी बनी। अभी आरसीबी 13 मैचों में 18 अंकों के साथ पहले नंबर पर काबिज है जिसमें उनका नेट रनरेट 1.065 का है और ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में जीत हासिल करने के साथ वह टॉप पोजीशन पर ही खत्म करेंगे जिसमें उनके कुल 20 अंक होंगे।

शादी की शर्त ने मचाया बवाल

अपर कास्ट या फिर 80 लाख की कमाई जरूरी

क्या आज भी शादी में प्यार से ज्यादा जाति और पैसा मायने रखते हैं? हाल ही में सामने आई एक घटना ने इसी सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया है. एक पढ़ी-लिखी और सफल महिला ने अपनी शादी के लिए ऐसी शर्त रख दी, जिसने आधुनिक सोच पर सवाल खड़े कर दिए- या तो दूल्हा 'उच्च जाति' का हो, वरना उसकी कमाई 80 लाख रुपये सालाना होनी चाहिए. इस एक शर्त ने दिखा दिया कि आज भी समाज में जाति और स्टेटस की सोच कितनी गहराई से जुड़ी हुई है, भले ही हम खुद को कितना भी प्रगतिशील क्यों न मान लें.

कहानी एक 32 साल की महिला की है, जो अपना खुद का फैशन बिजनेस चलाती है. वह एक अच्छे और पढ़े-लिखे परिवार से आती है. उसके पिता आईपीएस अधिकारी हैं और मां एक टीचर हैं. यानी बाहर से देखने पर वह एक आधुनिक और प्रगतिशील सोच वाले परिवार की लगती है. लेकिन जब बात शादी की आई, तो उसने दूल्हे के लिए एक खास शर्त रखी. ⊙

3 लाख महीना भी पड़ रहा कम

कपल ने महंगाई के डर से चुना 'नो किड्स' फॉर्मूला

आज के समय में बढ़ती महंगाई और ऊंचे खर्चों ने लोगों की जिंदगी के बड़े फैसलों को भी बदल दिया है. जहां पहले शादी के बाद बच्चा होना एक सामान्य बात मानी जाती थी, वहीं अब कई कपल इस पर दोबारा सोच रहे हैं.

गुरुग्राम के एक कपल ने भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया है, अच्छी खासी कमाई होने के बावजूद उन्होंने बच्चा न करने का निर्णय लिया, और इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. गुरुग्राम में रहने वाले एक दंपत्ति ने बच्चा न करने का फैसला लिया है, और इसकी वजह है बढ़ती महंगाई और खर्चे. इस दंपत्ति की सालाना कमाई करीब 36 लाख रुपये है, जो सुनने में काफी अच्छी लगती है. पति हर महीने लगभग 2 लाख रुपये कमाते हैं और पत्नी 1 लाख रुपये कमाती हैं. लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि वे अभी बच्चे का खर्च नहीं उठा सकते.

इस बात को उनके रिश्तेदार हर्ष गुप्ता ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद यह मुद्दा चर्चा में आ गया. उन्होंने बताया कि कागजों पर तो यह दंपत्ति आर्थिक रूप से मजबूत लगता है, लेकिन असल जिंदगी में खर्च इतने ज्यादा हैं कि वे परिवार बढ़ाने से बच रहे हैं. कपल का कहना है कि गुरुग्राम जैसे शहर में एक अच्छा घर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है. उन्होंने बताया कि वे एक ठीक-ठाक 1BHK फ्लैट भी नहीं खरीद पा रहे हैं. ऐसे में उनका सवाल है कि जब वे खुद के लिए सही जगह नहीं ले पा रहे, तो बच्चे के लिए बेहतर माहौल कैसे देंगे. इसके अलावा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बहुत ज्यादा है.

प्राइवेट स्कूलों की फीस हर महीने करीब 35,000 से 40,000 रुपये तक हो सकती है, जो उनके लिए उनके लिए संभालना मुश्किल है. यही कारण है कि उन्होंने अभी बच्चा न करने का फैसला लिया है. आजकल ऐसे कई शहरी कपल हैं, जो डबल इनकम, नो किड्स यानी DINK लाइफस्टाइल अपना रहे हैं. ⊙

दिल्ली मेट्रो की लड़ाई वायरल, भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

बहस के बाद लड़की ने जड़ा बुजुर्ग को थप्पड़

आए दिन दिल्ली मेट्रो में लड़ाई-झगड़े या बहस के वीडियो सामने आते रहते हैं. एक ऐसा ही वीडियो चर्चमा में है, जिसमें एक लड़की सीट को लेकर एक शख्स को थप्पड़ लगाती दिख रही है.

दिल्ली मेट्रो में लड़ाई-झगड़े से जुड़े वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. आए दिन कोई बहस, डांस या झगड़े का वीडियो सामने आते रहते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने मेट्रो में सफर कर रहे एक शख्स को थप्पड़ लगा दिया.

सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो घूम रहा है. इसमें सीट को लेकर एक महिला और एक पुरुष के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है. देखते ही देखते यह बहस हाथापाई में तब्दील हो गई. जब महिला ने शख्स को थप्पड़ जड़ दिया. इस घटना का किसी यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. उसके बाद से यह वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ghar-kekalesh नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसका कैप्शन है - दिल्ली मेट्रो के अंदर सीट को लेकर लड़की और अंकल के बीच कलेश. इस वीडियो में मेट्रो में सीट को लेकर एक लड़की और सीट पर बैठे शख्स के बीच तीखी बहस होती दिखाई देती है. फिर अचानक से लड़की उस आदमी को थप्पड़ लगा देती है.

इसके बाद वो शख्स भी खड़ा हो जाता है और लड़की को मारने के लिए हाथ उठाता है, फिर हाथ रोक लेता है. दोनों के बीच में एक महिला बीच-बचाव करती दिखाई देती है. लड़की लगातार ऊंची आवाज में सामने बैठे शख्स से बहस करती रह जाती है. इसके बाद उस शख्स को आसपास के लोग समझाकर बैठा देते हैं और लड़की आगे बढ़ जाती है. ⊙

टकराव हाथापाई में तब्दील

जैसे-जैसे लड़की का गुस्सा बढ़ता गया, टकराव हाथापाई में तब्दील हो गई. एक समय ऐसा भी आया जब महिला ने बहस के दौरान पुरुष को थप्पड़ मार दिया. पुरुष तुरंत अपनी सीट से उठा और उसकी ओर बढ़ा, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई. इस वीडियो पर काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने लिखा है - दिल्ली मेट्रो को ऐसे झगड़ों के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए. ⊙

स्नेक शो में सपेरे के हाथ से भागा सांप, टूरिस्ट को डसा

इजिप्ट में के एक रिसोर्ट में हाल ही में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई. इजिप्ट के पिरामिड देखने और वहां घूमने आए एक जर्मन टूरिस्ट की विचित्र तरीके से मौत हो गई. वह शख्स रिसोर्ट में सांप के करतब (स्नेक शो) देख रहा था. यह स्नेक शो उसके टूर पैकेज के एक एक्सक्लूसिव ऑफर का हिस्सा था. करतब के दौरान जब सपेरा सांप को टूरिस्ट के नजदीक ले गया तो वह फिसकर उसके पैंट में घुस गया और उसे काट लिया. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि एक जर्मन पर्यटक की तब मौत हो गई. ⊙

'कॉकरोच जनता पार्टी' से कोंकणा सेन शर्मा ने बनाई दूरी सोशल मीडिया पर तेज हुई चर्चाएं

सोशल मीडिया पर इन दिनों 'कॉकरोच जनता पार्टी' (C J P) नाम का एक काल्पनिक राजनीतिक और व्यंग्यपूर्ण आंदोलन जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। आम जनता से लेकर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां इस डिजिटल मूवमेंट का हिस्सा बनी हुई हैं। लेकिन इसी बीच एक नई हलचल देखने को मिली है। मशहूर अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा ने इस वायरल अकाउंट को अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद इंटरनेट पर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि कोंकणा इस अकाउंट को छोड़ने वाली पहली बड़ी हस्ती बन गई हैं, जबकि अनुराग कश्यप, दीया मिर्जा और ईशा गुप्ता जैसी हस्तियां अब भी इसे फॉलो कर रही हैं। CJP एक काल्पनिक, व्यंग्य-आधारित राजनीतिक आंदोलन है जिसे डिजिटल रणनीतिकार अभिजीत दिपके ने शुरू किया है। मई 2026 में, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणियों पर एक व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया के बाद इसे ऑनलाइन काफी लोकप्रियता मिली। यह आंदोलन वर्तमान में दो अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से चलाया जा रहा है। 'मेट्रो... इन दिनों' की अभिनेत्री का नाम शुरुआत में इस पार्टी के फॉलोअर्स की सूची में शामिल था, लेकिन बाद में उनका नाम इस सूची से गायब हो गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने इस अकाउंट को अनफॉलो कर दिया है। यह आंदोलन एक गैर-सत्यापित (non-verified) और एक सत्यापित (verified) अकाउंट के माध्यम से चलाया जाता है। जहाँ गैर-सत्यापित अकाउंट के लगभग 19.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं सत्यापित अकाउंट के लगभग 825,000 फॉलोअर्स हैं। कोंकणा ने इस अकाउंट को अनफॉलो करने का फैसला करने से पहले, इसके गैर-सत्यापित अकाउंट को फॉलो किया हुआ था। कोंकणा के अलावा, टीवी अभिनेता अभिषेक निगम ने भी इस पार्टी के अकाउंट को अनफॉलो कर दिया है। इस पार्टी के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करने वालों में फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप, अभिनेता दीया मिर्जा, ईशा गुप्ता और फातिमा सना शेख, निर्देशक कुणाल कोहली और हास्य कलाकार कुणाल कामरा शामिल हैं। टीवी जगत की हस्तियाँ, जिनमें उमर रियाज, उर्फी जावेद, हिमांशी खुराना और शीज़ान खान शामिल हैं, उन्होंने भी इस काल्पनिक राजनीतिक संगठन से जुड़ी ऑनलाइन चर्चाओं में हिस्सा लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी हाल ही में सोशल मीडिया पर तब वायरल हुई, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की कुछ विवादास्पद टिप्पणियों ने ऑनलाइन व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया। इन टिप्पणियों में उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले युवा भारतीयों की तुलना "कॉकरोच" और "परजीवियों" से की थी। इसके बाद अभिजीत दिपके ने इस मीम-आधारित राजनीतिक व्यंग्य आंदोलन की शुरुआत की।

पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी पर सपा का सरकार के खिलाफ मोर्चा

लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी ने NEET पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल-डीजल व गैस की बढ़ती कीमतों और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। पुलिस से धक्का-मुक्की के बाद कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेजा गया। सपा नेताओं ने सरकार पर युवाओं और ओबीसी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया।

लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने हजरतगंज चौराहे पर नीट परीक्षा लीक और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी, छात्र सभा और यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाथों में सरकार विरोधी पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो काफी देर तक धक्का-मुक्की हुई। कई कार्यकर्ता पुलिस बस की छत पर चढ़ गए। पुलिसकर्मियों ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेज दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने सड़क पर घसीटा, इससे उनके कपड़े फट गए और हाथ छिल गए। समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव आनंद यादव ने बताया कि भाजपा सरकार में लगातार महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। खाने-पीने की वस्तुएं भी लगातार महंगी होती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती सहित कई भर्तियां पिछले कई वर्षों से लंबित हैं, लेकिन सरकार ओबीसी वर्ग के हक को लागू नहीं कर रही है और न ही उन्हें जॉइनिंग दे रही है। साथ ही, अखिलेश यादव द्वारा पत्रकार वार्ता में मुद्दा उठाने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ही जाति के तीन लोगों को तीन विश्वविद्यालयों का कुलपति नियुक्त किया है। समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव राज साहनी ने बताया कि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, NEET परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, उसके विरोध में हम समाजवादी लोग आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हत्याएं और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जबरन हमें बसों में भरकर ले जाने का काम किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता जीतू कश्यप ने बताया कि आपने देखा, NEET का पेपर लीक हुआ, जिससे 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री छात्रों से मिलने के बजाय मेलोनी को गिफ्ट देने में व्यस्त हैं। आखिर कोई प्रधानमंत्री ऐसा कैसे हो सकता है? इसी विरोध में आज हम 100 रुपए में डिग्री बेचने आए हैं। जब से भाजपा सरकार आई है, तब से 70-80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इससे युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है और नौकरी मिलने की उम्मीद खत्म होती जा रही है। सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल रही है। यह सरकार की बड़ी नाकामी है और सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट परीक्षा रद्द और पेपर लीक, महंगे पेट्रोल डीजल, गैस के दाम, दूध के दाम की बढ़ोतरी और महिला सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथ में पोस्टर लेकर पहुंचे जिस पर लिखा था 'महंगाई की यह कैसी मार, मजे में नेता जनता बेलाचार'। 'पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम सरकार नाकाम'।

लखनऊ में प्रचंड गर्मी, पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में पिछले साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। गुरुवार को सीजन का सबसे अधिक तापमान 43.6 डिग्री रहा। पिछले साल मई में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री दर्ज किया गया था। आज सुबह से भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह से तेज धूप निकली है। गर्म हवाओं के थपेड़े पड़ रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से लू चलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान सीजन में सबसे अधिक आज दर्ज हो सकता है। 31 मई 1995 का 46.5 डिग्री का आल टाइम रिकॉर्ड भी टूटने की संभावना बनी हुई है। डीएम ने सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी करने का निर्देश दिया है। इमरजेंसी के लिए अस्पतालों में वार्ड रिजर्व किए गए हैं। गुरुवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम आर्द्रता 59 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 15 फीसदी रही। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अब आने वाले दिनों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। आज दिन में लू के हालात बने रहेंगे। पूर्वी यूपी में साइक्लोनिक प्रेशर होने के साथ में ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण वास्तविक तापमान आभासी तापमान से अधिक लग रहा है।

8 महीने से रिजल्ट का इंतजार

अभ्यर्थियों ने किया UPSSSC कार्यालय का घेराव

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती 2024 का परिणाम जारी न होने से नाराज अभ्यर्थियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। शुक्रवार सुबह 9 बजे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गोमतीनगर स्थित पिकअप भवन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) कार्यालय का घेराव किया। अंतिम परिणाम जल्द घोषित करने की मांग उठाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि 8 महीने से वे अनिश्चितता और मानसिक दबाव में जी रहे हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक, इस भर्ती प्रक्रिया के तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) करीब 8 महीने पहले ही पूरा हो चुका है। अब तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई है। उनका कहना है कि सामान्य प्रक्रिया में इतना लंबा समय लगना असामान्य है और इससे आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि रिजल्ट में देरी ने उन्हें सफलता और असफलता के बीच लटका दिया है। लगातार इंतजार के कारण मानसिक तनाव, अवसाद और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि वे न तो अन्य विकल्प चुन पा रहे हैं और न ही आगे की योजना बना पा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से परिणाम न आने के कारण उन पर आर्थिक और पारिवारिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। खासकर ग्रामीण और कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवारों के लिए यह स्थिति और भी कठिन होती जा रही है। परिवार और समाज के सवालों के

बीच वे लगातार दबाव झेल रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार की 'मिशन रोजगार' नीति का हवाला देते हुए आयोग से अपील की है कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए इस भर्ती को प्राथमिकता पर लिया जाए और जल्द से जल्द अंतिम परिणाम घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परीक्षा का रिजल्ट नहीं, बल्कि सैकड़ों युवाओं के करियर और जीवन का सवाल है।

स्कूलों की मनमानी फीस पर प्रशासन सख्त, 8 स्कूलों को नोटिस

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में हुई जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में 20 स्कूलों के खिलाफ आई शिकायतों की समीक्षा की गई। 8 स्कूलों शिकायतें सही पाई गईं। इन स्कूलों को नोटिस जारी कर 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई। इनमें से 2 स्कूलों ने लिखित में दिया है कि बढ़ाई गई फीस को अगले महीने की फीस में समायोजित किया जाएगा। जिला शुल्क नियामक समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, बाकी स्कूलों पर लगे आरोप साबित नहीं हुए। जांच में दोषी पाए गए स्कूलों में से 2 स्कूलों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बढ़ाई गई फीस का समायोजन अगले माह किया जाएगा, ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन 8 स्कूलों के खिलाफ शिकायतें सही पाई गई हैं, उन्हें नोटिस जारी कर पूछा जाए कि उनके खिलाफ 5 लाख रुपये का जुर्माना क्यों न लगाया जाए? सभी स्कूलों को 1 जून 2026 तक अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है।

लखनऊ में छात्रा से दुष्कर्म मामला, अस्पताल सील, डॉक्टर जेल भेजा गया

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में 12वीं की छात्रा से रेप के आरोपी डॉक्टर को जेल भेज दिया गया है। पीड़िता के मुताबिक, डॉक्टर ने उसके साथ ऑपरेशन थियेटर में रेप की वारदात की। मामले में डिप्टी सीएम के दखल के बाद स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने प्राइवेट हॉस्पिटल को सील कर दिया है। डॉक्टर की डिग्री और लाइसेंस भी कैंसिल किया गया है। घटना बक्शी का तालाब के इंदौराबाग स्थित तेजस हॉस्पिटल की है। पीड़िता के पिता के मुताबिक, उनकी बेटी को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। उसे इलाज के लिए 19 मई को तेजस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 21 मई को हॉस्पिटल में दोपहर करीब 3 बजे बेटी को अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई। ऑक्सीजन लगाने के बहाने डॉ. विजय गिरी बेटी को ऑपरेशन थिएटर में ले गया। उसके साथ बड़ी बेटी और एक नर्स भी गई थी। लेकिन कुछ ही देर बाद डॉ. विजय गिरी ने नर्स और बड़ी बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने पुलिस को बताया कि डॉ. विजय गिरी ने बेटी की कलाई में लगे वीगो से उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया। इसके बाद बेटी को कुछ होश नहीं रहा। कुछ देर बाद जब होश आया तो वह ऑपरेशन थिएटर से भागते हुए बाहर आई। उसने रोते हुए हम लोगों को बताया कि डॉक्टर ने उसके साथ रेप किया है। इसके बाद हम लोगों ने घटना की शिकायत पुलिस से की। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में कहा- डॉक्टर ने इलाज के बहाने पहले गंदी नीयत से शरीर पर हाथ लगाया। ओटी में मेरे साथ गई बहन को बाहर कर दिया। फिर बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद दुष्कर्म किया।

ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश, साइकिल से कोर्ट पहुंचे जज

लखनऊ में शुक्रवार को जिले के करीब 70 जज साइकिल से कोर्ट के लिए रवाना हुए। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती खपत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह अनोखा अभियान चलाया गया। जिला जज मलखान सिंह के नेतृत्व में शुरू हुए इस कार्यक्रम को हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला जज मलखान सिंह के डालीबाग स्थित आवास पर सभी जज इकट्ठा हुए। जिला जज के नेतृत्व में सभी जज सुबह 9 बजे साइकिल से कोर्ट के लिए निकले। इस दौरान सभी जजों ने आम लोगों को ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। लखनऊ हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश चौहान ने इस अभियान की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। उन्होंने इसे एक सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में जागरूकता लाने के लिए बेहद जरूरी हैं। अभियान में शामिल होने के लिए जिन जजों को साइकिल चलाना नहीं आता था,

वे ई-रिक्शा से कोर्ट पहुंचे। वहीं, कई वकील भी इस पहल से जुड़े और साइकिल या ई-रिक्शा से अदालत पहुंचे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा के अनुसार, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बढ़ते ईंधन संकट के प्रति लोगों को जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर की गई अपील से भी प्रेरित है। न्यायिक अधिकारियों ने इस माध्यम से आम जनता को वैकल्पिक साधनों को अपनाने का संदेश दिया।

सांसद साक्षी महाराज ने विकास कार्यों और जनसमस्याओं पर की चर्चा

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज की अध्यक्षता में शुक्रवार को विकास भवन सभागार में दिशा समिति की बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जनसमस्याओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के बाद सांसद साक्षी महाराज ने बताया कि दिशा समिति की बैठकें हर तीन माह में आयोजित की जाती हैं। इनका उद्देश्य भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करना है। जनप्रतिनिधि और समिति सदस्य मिलकर जिले की ज्वलंत समस्याओं और विकास कार्यों की कमियों को उठाते हैं, ताकि उनका समयबद्ध समाधान हो सके। सांसद ने आगे कहा कि बैठक में उठाए गए मुद्दों को जिलाधिकारी द्वारा नोट किया जाता है और उसी आधार पर कार्रवाई होती है। यदि किसी कार्य में लापरवाही या दोष पाया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और अधूरे कार्यों को पूरा कराया जाता है। सांसद ने नवागत जिलाधिकारी की कार्यशैली की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि वे अपनी टीम के साथ जिले की समस्याओं का प्रभावी समाधान करेंगे। सांसद ने पत्रकारों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं।

यदि कोई समस्या अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों की जानकारी से छूट जाती है, तो मीडिया उसे सामने लाता है, जिससे समाधान में मदद मिलती है। बैठक के दौरान बिजली व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सांसद ने कहा कि बिजली समस्या केवल जनता की नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की भी है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ इस संबंध में चर्चा की गई है और समस्या के समाधान के लिए अलग से एक और बैठक की जाएगी। तालाबों और पोखरों पर हो रहे अतिक्रमण के सवाल पर सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि बरसात का मौसम आने वाला है। ऐसे में सरकार की नीति "खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में" को प्रभावी ढंग से लागू करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि तालाबों और पोखरों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि जल संरक्षण हो सके और भूजल स्तर बना रहे। साथ ही गोचर भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठाई गई, जिससे गौसेवा के लिए भूमि सुरक्षित रह सके। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, "दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है।" उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 300 पार सीटें हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और पूर्व की सरकारों के कार्यकाल को नहीं भूली है।

उन्नाव बाजार में दो पक्षों में मारपीट

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र की बदरका चौकी अंतर्गत बंथर बाजार में दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने लगे और जमकर मारपीट हुई। इस घटना में कई युवक घायल हो गए। बाजार में अचानक हुई मारपीट से अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बंथर बाजार में किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई थी। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते लाठी-डंडों से हमला शुरू हो गया। मारपीट के दौरान बाजार में काफी देर तक हंगामा होता रहा। आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमला करते रहे। घटना में कई युवकों के चोटिल होने की जानकारी सामने आई है। कुछ घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। मारपीट की घटना से बाजार में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस नहीं पहुंचती तो विवाद और बढ़ सकता था। सूचना मिलते ही अचलगंज थाना पुलिस और बदरका चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों के बारे में जानकारी जुटाई। घटना के बाद कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

उन्नाव को स्वच्छ बनाने की तैयारी तेज

जनपद को स्वच्छ, सुंदर और कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रोजेक्ट कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने विस्तृत प्रस्तुतीकरण देखा और शहरों की सफाई व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से बेहतर बनाने पर चर्चा की। बैठक में 'लाइन सर्विस लिमिटेड' और 'वेस्ट एक्स इंडिया' नामक प्रोजेक्ट कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपनी योजनाओं का प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, मैनुअल और मशीन स्वीपिंग, नाली सफाई, कचरा प्रबंधन, जीपीएस व जीआईएस मॉनिटरिंग, कंट्रोल रूम और लाइव मैपिंग सर्वे जैसे विभिन्न कार्य शामिल थे। कंपनियों ने बताया कि इस अभियान के तहत घरों से सूखा और गीला कचरा अलग-अलग एकत्र कर वैज्ञानिक विधि से उसका निस्तारण किया जाएगा। कंपनियों ने यह भी जानकारी दी कि प्रशिक्षित कर्मचारी निर्धारित समय पर घरों, दुकानों और संस्थानों से नियमित रूप से कूड़ा एकत्र करेंगे। इसके लिए आधुनिक कूड़ा संग्रहण वाहनों और पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाएगा, जिससे प्रदूषण कम करने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इस योजना में बेहतर सेवाओं के साथ यूजर चार्ज वसूल कर नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जोर दिया कि जनपद उन्नाव स्वच्छ, सुंदर और साफ-सुथरा दिखना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि कहीं भी झाड़ियां, गंदगी या कूड़े के ढेर नजर नहीं आने चाहिए। इसके लिए सभी अधिशासी अधिकारी नगर निकायों और प्रोजेक्ट कंपनियों के साथ बैठक कर एक ठोस रणनीति तैयार करें। उन्होंने कहा कि एक प्रभावी सफाई व्यवस्था लागू करने के लिए सर्वे कर बेहतर योजना प्रस्तुत की जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे उन शहरों का दौरा करें जहां ये कंपनियां पहले से कार्यरत हैं। वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर प्राप्त अनुभव के आधार पर उन्नाव में एक बेहतर मॉडल लागू किया जाए। उन्होंने नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। अपील की जाएगी कि वे गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखें और शहर को साफ रखने में सहयोग करें।

उन्नाव में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी शोरूम में लगी आग

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के सोहरामऊ कस्बे में शुक्रवार को एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेज़ थी कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया और आसपास की कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी शोरूम से उठती दिखाई दी। कुछ ही देर में धुएं का गुबार पूरे क्षेत्र में फैल गया। आग की लपटें इतनी तेज़ थीं कि बगल में स्थित बाला जी स्टूडियो सहित कई अन्य प्रतिष्ठानों तक पहुंच गईं। दुकानदारों ने आनन-फानन में अपनी दुकानों से सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया, जबकि मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड और सोहरामऊ थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो चुका था। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, बैटरियां, फर्नीचर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचा है। आग की चपेट में आई अन्य दुकानों में भी क्षति की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। फायर विभाग और पुलिस मामले की जांच कर रही है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के दौरान हाईवे किनारे काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही, जिसे पुलिस ने यातायात नियंत्रित कर सामान्य किया। आग बुझने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं, प्रभावित व्यापारियों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर उचित सहायता प्रदान करने की मांग की है।

उन्नाव डीएम ने गौशालाओं की व्यवस्था पर जताई नाराजगी

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के डीएम घनश्याम मीना ने गौवंश संरक्षण और संवर्धन को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों और पशु चिकित्सकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। विकास भवन सभागार में हुई इस बैठक में गौशालाओं की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने गौशालाओं में पाई गई लापरवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार के तत्काल निर्देश दिए। बैठक के दौरान, जिलाधिकारी ने अधिकारियों और डॉक्टरों से प्रत्येक गौशाला के निरीक्षण, हरे चारे, भूसे, टीन शेड, पेयजल, सीसीटीवी कैमरे, बीमार पशुओं के इलाज और मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। समीक्षा में यह सामने आया कि कुछ गौशालाओं में पशुओं को केवल सूखा भूसा दिया जा रहा था, जबकि हरे चारे, खली और चोकर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। इस पर जिलाधिकारी ने गंभीर आपत्ति जताई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गौवंश संरक्षण शासन की प्राथमिकताओं में से एक है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी गौशालाओं में पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध कराया जाए और पशुओं को भूसे के साथ हरा चारा, चोकर तथा खली मिलाकर खिलाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कहीं भी केवल सूखा भूसा दिए जाने की शिकायत मिली, तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्नाव में अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण नाराज

उन्नाव जिले में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा देर रात फूट पड़ा। बिजली संकट से त्रस्त ग्रामीणों ने जिलाधिकारी आवास का घेराव कर तत्काल समस्या के समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी घनश्याम मीना को बताया कि कई क्षेत्रों में घंटों तक बिना सूचना बिजली कटौती की जा रही है। भीषण गर्मी में बिजली न मिलने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार, बिजली कटौती के कारण पेयजल संकट गहरा गया है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते उन्हें देर रात डीएम आवास पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने सीयूजी नंबर पर आने वाली कॉल का अनिवार्य रूप से जवाब दें। डीएम ने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी ने फोन रिसीव नहीं किया या शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरती, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता की सुविधा के लिए जिलाधिकारी ने 1912 हेल्पलाइन के अतिरिक्त नया नंबर 9415710542 भी जारी किया है। इस नंबर पर लोग बिजली संबंधी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर, सीएम योगी ने राहत व्यवस्था पर दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखते हुए अस्पतालों, पेयजल और बिजली आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को लू प्रभावित मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने और जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में सतर्क रहने को कहा। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार, जिला मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और राहत एजेंसियों को उच्च सतर्कता बरतनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश में कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को अस्पतालों, पेयजल आपूर्ति और बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है और सरकारी अस्पतालों में लू लगने से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशों में जनता से लू से बचाव के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने आदेश में कहा कि बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल पर विशेष ध्यान दें, सूती या खादी के ढीले-ढाले कपड़े पहनें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी ऐसी लापरवाही भरी हरकत में शामिल न हों जिससे आग लगने का खतरा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को कर्मचारियों को थकान, निर्जलीकरण और लू से बचाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका है। राज्य भर में भीषण गर्मी के बीच बांदा में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे यह देश का सबसे गर्म स्थान बन गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार दोपहर को राज्य के कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। झांसी में 44.6 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 44.5 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 44.2 डिग्री, ओराई में 43.8 डिग्री, सुल्तानपुर में 43.3 डिग्री और वाराणसी (भुवन वर्ष) में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। विभाग ने कहा कि राज्य भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर लू चलने की प्रबल संभावना है। रविवार को जारी मौसम चेतावनी में कहा गया है कि प्रयागराज, गाजीपुर, ओराई और आगरा में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा, जबकि इटावा और मेरठ में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा।

गंगा में नहाते-नहाते युवक ने बीयर पी, FIR दर्ज

काशी में गंगा नदी में इफ्तार पार्टी के बाद शुक्रवार को बीयर पीने का मामला सामने आया है। अस्सी घाट गंगा में नहा रहे एक युवक ने बीयर पी। फिर केन को मोड़कर गंगा के तट पर फेंक दिया। युवक की इस करतूत को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। उसे नदी से बाहर अपने पास बुलाया और फटकार लगाई। आरोपी युवक ने माफी मांगी। उसने कहा, गलती हो गई। अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा। वीडियो सामने आने के बाद वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में युवक पर केस दर्ज किया है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम लगाई गई है। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी युवक बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला है। संतों की कहना है कि यह आस्था का अपमान है। ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। वहीं, कांग्रेस ने X पोस्ट में लिखा, योगी जी बताएं। आस्था के केंद्र को हुड़दंगियों का अड्डा बनाने के लिए आपको क्यों न जिम्मेदार ठहराया जाए? काशी के रहने वाले वकील और शिकायकर्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा, मां गंगा हिंदू धर्म में आस्था और पूजा का केंद्र है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुबह करीब 5 बजे एक युवक गंगा में नहा रहा है। उसके हाथ में बीयर की एक केन है। वह नहाते समय बीयर पी रहा है, यह ठीक नहीं है। गंगा घाटों पर इस तरह का कृत्य करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। यह वीडियो धार्मिक माहौल को दूषित करने और सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाला है। अगर ऐसे मामलों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ेगा। कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आरोपी पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। साथ ही घाटों पर निगरानी बढ़ाएं।

बाहुबलियों को मिले शस्त्र लाइसेंस पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजा भैया, बृजभूषण, धनंजय सिंह समेत 50 से ज्यादा बाहुबलियों की क्राइम कुंडली यूपी सरकार से मांगी है। कोर्ट ने बाहुबलियों के गन लाइसेंस और सुरक्षा की भी जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने गृह विभाग के अफसरों को फटकार लगाते हुए 26 मई तक जांच रिपोर्ट जमा करने को कहा है। साथ ही गृह विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी हलफनामा के साथ संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों और कमिश्नरेट के कमिश्नरों की अंडरटेकिंग (लिखित जिम्मेदारी) भी देंगे। दरअसल, संत कबीरनगर के रहने वाले जयशंकर उर्फ बैरिस्टर ने गन लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 18 मई को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने यह दिया। 20 मई को यह आदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ। सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा देखकर हाईकोर्ट ने हैरानी जताई। गृह विभाग ने हलफनामे में बताया था कि इस समय प्रदेश में करीब 10 लाख से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी हैं। अभी भी 23 हजार से अधिक आवेदन लंबित पड़े हैं। 6 हजार से ज्यादा ऐसे लोगों को भी लाइसेंस दिए गए हैं, जिन पर दो या उससे अधिक आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसके अलावा, प्रदेश में करीब 21 हजार परिवार ऐसे हैं, जिनके पास एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस हैं। पुलिस और डीएम के फैसलों के खिलाफ 1,738 अपीलें अभी कमिश्नरों के पास लंबित हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा- 26 मई तक जोनवार और जिला या थानावार बाहुबलियों और आपराधिक केस वाले लोगों की लिस्ट दें, जिनको गन लाइसेंस और सुरक्षा दी गई है। गृह विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी हलफनामा के साथ संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों और कमिश्नरेट के कमिश्नरों की अंडरटेकिंग (जिम्मेदारी) भी देंगे। संबंधित जिलों के पुलिस कप्तान या कमिश्नरेट के कमिश्नर जानकारी देते हुए यह अंडरटेकिंग देंगे कि कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। अगर छिपाया गया तो वह खुद जिम्मेदार होंगे।

बाराबंकी में बंदूक की नोक पर 1.02 करोड़ की डकैती

बाराबंकी में बंदूक की नोक पर नकाबपोश डकैतों ने शुक्रवार तड़के 3 बजे किराना व्यापारी के घर से 1.02 करोड़ लूट लिए। 7 बदमाश दो मंजिला घर के पिछले दरवाजे को तोड़कर घुसे। सो रहे लोगों को उठाया। उन्हें पीटा। उन पर बंदूक तान दी। हाथ-पैर रस्सी से बांधकर मुंह पर टेप लगा दिया। कहा- अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो गोली मारकर ढेर कर देंगे। घर में मौजूद छोटे बच्चे (व्यापारी के नाती) जब डरकर रोने लगे तो डकैतों ने उन्हें भी बेरहमी से पीटा। उनकी मां को कहा- इन्हें दूध पिलाकर चुप कराओ, वरना गोली मार देंगे। इसके बाद व्यापारी के इकलौते बेटे के सिर पर तमंचा रखकर कहा- चुप रहना नहीं तो पूरे परिवार को मारकर दफन कर देंगे। डकैतों ने करीब एक घंटे तक घर के हर कमरे को खंगाला। 12 लाख रुपए कैश और 90 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। किसी तरह व्यापारी के परिवार ने रस्सी खोलकर पुलिस को सूचना दी। मौक पर SP, ASP, CO पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। डकैतों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। मामला देवा थाना क्षेत्र का है। ग्वारी गांव में किराना कारोबारी आलोक जायसवाल (52) का मकान है। ग्राउंड फ्लोर पर किराने की थोक दुकान और गोदाम है। ऊपर की मंजिल पर अपनी मां नंदिनी जायसवाल (74), पत्नी नीलम (45), बेटे हिमांशु (28) और बहू नेहा उर्फ प्रियंका (25) के साथ रहते हैं। उनकी दो बेटियां सोनाली (29) और देवांशी (26) भी हैं। दोनों की शादी हो चुकी है। दोनों अपने बच्चों के साथ 3 दिन पहले ही गर्मी की छुट्टियों में मायके आई थीं। आलोक के साले के बेटी आराधना जायसवाल (7) भी घर आई हुई थी।